वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिजली दरों के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग की सार्वजनिक सुनवाई में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से Suggested Points

बिहार में बिजली वितरण कंपनियॉ यानी नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL)एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL)ने वित्तीय वर्ष 2022-23के लिए वार्षिक टैरिफ याचिकाएं प्रस्तुत की हैं जिन्हें 1 अप्रैल 2022 से लागू किया जाएगा। इस संबंध में, हमारा निम्नलिखित सुझाव हैं:—

1. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने 2018-19 में 99.53%राजस्व का संग्रह किया था जो 2019-20 में घटकर 73.74% और 2020-21 में 85.33% रह गई है । इससे साफ जाहिर होता है कि Aggregate Transmission and Commercial (AT&C) का बहुत अधिक नुकसान हुआ है। राजस्व संग्रहण की क्षमता को बढ़ाना एक मुख्य कारक है, इसे प्राथमिकता के आधार पर सुधारा जाना चाहिए ताकि बहुमुल्य राष्ट्रीय संसाधनों की बर्बादी को रोका जा सके।

2. एचटी औद्योगिक इकाइयों को यदि24x7 बिजली की आपूर्ति उपलब्ध कराई जाती है तो इससे राजस्व में अधिकाधिक वृद्धि होगी। यह सर्वविदित है कि बिहार के आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि अच्छी गुणवत्ता का बिजली उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए । अतः सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। BERC द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उच्च मूल्य का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को अप्रतिस्पर्धी न बनाया जाए और औद्योगिक इकाइयों को निर्बाध बिजली की आपूर्ति नहीं करने पर DISCOMS पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

3. वितरण हानि को BERC द्वारा निर्धारित 15% के अनुसार ही माना जाना चाहिए न कि DISCOMS द्वारा दावा किए गए के अनुसार। ईमानदारी से भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं पर बिजली के उंचे दर को लागू कर उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि AT&C घाटे को नियंत्रित करने में DISCOM विफल रहा है और उस घाटे को नियंत्रित करने पर हजारों करोड़ का सार्वजनिक धन का खर्च किया गया है।

5. बिजली आपूर्ति की पूर्व भुगतान प्रणाली (Pre-paid metering) के संबंध में हमारा सुझाव है कि

   (i) इस प्रकार का प्रावधान वैकल्पिक होना चाहिए ।

   (ii) पूर्व भुगतान प्रणाली की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए समय पर भुगतान के लिए पूर्व से मिल रहे 1.5% की छूट एवं ऑनलाइन भुगतान करने पर मिल रहे 1.00% की छूट के अतिरिक्त कम से कम 3% की छूट यानि कुल 5.5% की छूट दी जानी चाहिए ।

   छूट के उपरोक्त संदर्भ में, माननीय BERC डेलॉयट द्वारा फोरम ऑफ रेगुलेटर्स (एफओआर) के लिए किए गए अध्ययन पर फिर से विचार करना चाहेंगे जिसमें उन्होंने पोस्ट पेड उपभोक्ताओं को 5 से 6 प्रतिशत की छूट देने का सुझाव दिया है।

   (iii) प्रीपेड मीटरों का तेजी से चलने के संबंध में उपभोक्ता के भ्रम को दूर करने के लिए मीटर का परीक्षण किया जाना चाहिए और स्थापना के समय उपभोक्ता को परीक्षण का रिपोर्ट उपलब्ध करायी जानी चाहिए। अधिनियम की धारा 55 में सही मीटर लगाने की प्रक्रिया का प्रावधान है।

   (iv) Reducing Balance System पर अग्रिम भुगतान और रिचार्ज राशि पर 6% ब्याज की अनुमति दी जानी चाहिए और 2000/- रुपये की सीमा को हटाया जाना चाहिए। 2000/- रुपये से कम की राशि पर ब्याज न देने का कोई औचित्य नहीं है।

(v) हटाए गए पोस्टपेड मीटर की लागत को लाइसेंसधारियों के Assets से कम की जानी चाहिए।

5. माननीय आयोग के बार–बार के आदेश के बावजूद, SBPDCL और NBPDCL ने अभी तक एसेट रजिस्टर तैयार नहीं किया है। यह समझ में नहीं आता है कि वे परिसंपत्ति से संबंधित लागत और एआरआर के अन्य मानकों को कैसे पूरा कर रहे हैं।

6. टैरिफ याचिकाओं के अनुसार करीब छह (6) से आठ (8) लाख उपभोक्ता बिना मीटर के बिजली का उपयोग कर रहे हैं । यह तथ्य बहुत ही हैरान करने वाला है। हालांकि, ऐसे उपभोक्ताओं पर मीटर लगाने के बजाय, DISCOMS अपना पूरा ध्यान पटना और बिहार के कुछ अन्य शहरों में मीटर से जला रहे बिजली के मीटर को प्रीपेड मीटर से बदलने पर दे रहे हैं। जबकि बिना मीटर वाले किसी भी कनेक्शन को जारी रखना टैरिफ निर्धारण अधिनियम की धारा 55 के प्रावधान का उल्लंघन है । अत: DISCOMS को प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम बिना मीटर पर बिजली जला रहे उपभोक्ताओं को मीटर उपलब्ध कराना चाहिए।

7. BERC द्वारा निरंतर निगरानी के बावजूद, ट्रांसमिशन एवं और वितरण हानि घटने के बजाय बढ़ गई है। अब समय आ गया है कि BERC और राज्य सरकार इस कीमती राष्ट्रीय संसाधनों की बेवजह बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए दोषी अधिकारियों पर व्यक्तिगत दंड लगायें।

APDRP की शुरुआत के बाद से वर्ष 2006 से वितरण ट्रांसफार्मर पर मीटर लगाया गया है। हाल ही में निष्पादित योजनाओं जैसे IPDS, DDUGJY, RGGVY आदि ने वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) पर मीटर की स्थापना पर काफी राशि प्रदान की है। मुख्य उद्देश्य उस विशेष डीटीआर को पहचानना था जिस पर लाइन लॉस अधिक था। हालांकि, यह माननीय आयोग को अच्छी तरह से पता होगा कि क्या DISCOMS ने डीटीआर मीटरिंग पर लागत का उपयोग करने के लिए इस तरह की कवायद की है। इसलिए हमारा सुझाव है कि माननीय BERC को डीटीआर पर मीटर लगाने की उपयोगिता की जांच करनी चाहिए, और यदि डीटीआर मीटरिंग का कोई उपयोग नहीं है, तो DISCOMS द्वारा ली गई पूरी परियोजना जनता के पैसे की बर्बादी होगी।

8. पूर्ववर्ती BSEB को पहले से ही विभिन्न कंपनियों में पुनर्गठित किया गया है, जिसका उद्देश्य उत्तराधिकारी कंपनियों को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाना है। हालाँकि, यह उद्देश्य हासिल नहीं किया गया है क्योंकि DISCOM पर सरकारी नियुक्तियों का वर्चस्व बना हुआ है। पुनर्गठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, उद्योग और उपभोक्ता प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए इन कंपनियों के बोर्ड को व्यापक बनाया जाना चाहिए। Managing Director का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए और दीर्घकालिक व्यवहार्यता योजनाएं बनाई जानी चाहिए और उन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

9. वर्तमान में, सभी उपभोक्ताओं पर 6% की दर से Electricity Duty लगाया जाता है, जो एक असहनीय बोझ है, खासकर औद्योगिक उपभोक्ताओं पर। इसे जीएसटी का हिस्सा बनाकर Setoff सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, औद्योगिक इकाइयों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए इसे घटाकर 2 पैसे प्रति यूनिट किया जाना चाहिए।

10. वर्तमान में, ऊर्जा एक्सचेंजों के माध्यम से उन कीमतों पर बिजली खरीदी जा सकती है जो दीर्घकालिक समझौतों से कम हैं। इसलिए, हम BERC और DISCOM से अनुरोध करते हैं कि वे इसका लाभ उठाने के लिए अपनी तकनीकी और प्रबंधकीय प्रणालियों को अपग्रेड करें। इससे वे बिजली की लागत को कम करने में सक्षम होंगे, जिससे सभी उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

क्रमशः........3

11. ओपन एक्सेस को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए और BERC द्वारा यथानुपात केवीए शुल्क लगाने के लिए विनियमों को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए। इसके बिना किसी भी उपभोक्ता के लिए ओपन एक्सेस पावर खरीदना व्यवहार्य नहीं होगा। इससे डिस्कॉम को भी फायदा होगा क्योंकि उनकी शुद्ध बिजली खरीद लागत में कमी आएगी।

12. DISCOMS को ग्राहकोंपर ध्यान केंद्रित करने की तत्काल आवश्यकता है। डिस्कॉम की वेबसाइट पर टैरिफ और अन्य मानदंडों के सभी प्रासंगिक विवरण उपलब्ध होना चाहिए। फील्ड अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें नए नियमों के बारे में शिक्षित किया जा सके और उन्हें ग्राहकों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके। Escalation System के साथ एक केंद्रीकृत हेल्पलाइन और शिकायत निवारण तंत्र तुरंत शुरू किया जाना चाहिए।

13. किसी भी प्रकार के फिक्स चार्ज का पूरी तरह से हटायाजाना चाहिए क्योंकि DISCOM अब अपनी पूरी बिजली की आवश्यकता को खरीद रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रिड के वर्तमान युग में और केवल वास्तविक खपत के आधार पर डिस्कॉम द्वारा खरीद, डिस्कॉम को अपने निश्चित क्षमता शुल्क को कम करने के लिए अतिरिक्त PPA को रद्द करने का अनुरोध किया जाना चाहिए।

14. एचटी उपभोक्ता अभी भी 20% से अधिक की क्रॉस सब्सिडी का बोझ उठा रहे हैं। यह उन्हें अप्रतिस्पर्धी बना रहा है और इसके परिणामस्वरूप एचटी की खपत कुल बेची गई इकाइयों के 9 से 10% तक कम हो गई है। अत: 2 साल में क्रॉस सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाना चाहिए और इसे टैरिफ में से घटाकर अधिकतम +-10% कर दिया जाना चाहिए।

15. लोड फैक्टर छूट को और आकर्षक बनाया जाना चाहिए। वर्तमान लोड फैक्टर Rebate बहुत कम है और बहुत कम उपभोक्ताओं को ऊर्जा बिल का मुश्किल से 1% - 2% मिलता है। वास्तविक खपत केवीए और संपूर्ण ऊर्जा शुल्कों पर इसकी छूट देने के लिए वर्तमान लोड फैक्टर छूट को पुनर्गठित किया जा सकता है। सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जा सकती है LF में 30% से अधिक होने पर प्रत्येक 1% वृद्धि के लिए 1%पूरे खपत पर छूटी दी जानी चाहिए अधिकतम 20% तक । चूंकि एचटीएसएस में उपभोक्ताओं का लोड फैक्टर अधिक होता है, इसलिए उनके लिए न्यूनतम एलएफ 50% रखा जा सकता है। इस प्रकार का प्रावधान वर्तमान में झारखंड में अपनाया जा रहा है। छूट पूरे खपत पर एवं लोड फैक्टर की गणना खपत किये गये केवीए पर होना चाहिए ।

16. वर्तमान में लगभग सभी एचटी उपभोक्ताओं के परिसरों में संवेदनशील और उच्च गुणवत्ता वाले मीटर लगाए गए हैं जो केवीए, मांग, पावर फैक्टर, केवीएएच, केडब्ल्यूएच और अन्य बिलिंग मापदंडों की तत्काल रीडिंग देता है। यह डेटा स्थायी रूप से मीटर में संग्रहीत होता है जिसे एमआरआई के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। इसलिए, मांग आधारित टैरिफ एचटीएसएस उपभोक्ताओं सहित सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर लागू किया जाना चाहिए, चाहे उनका कनेक्टेड लोड कुछ भी हो। सभी एचटी उपभोक्ताओं के लिए रिमोट मीटर रीडिंग की शुरुआत की गई है और इसे सभी एनडीएस उपभोक्ताओं तक बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही सभी उपभोक्ताओं को मासिक बिजली बिल के साथ एमआरआई रिपोर्ट की कॉपी भी दी जानी चाहिए ।

17. एचटी उपभोक्ताओं द्वारा बढ़ी हुई यूनिट खपत को प्रोत्साहित करने के लिए, वर्तमान टीओडी संरचना को संशोधित किया जाना चाहिए। प्रतिदिन 6 घंटे के लिए 120% की दंड स्लैब को

क्रमशः........4

समाप्त कर दिया जाना चाहिए। साथ ही रात 11 बजे से सुबह 11 बजे तक 12 घंटे के लिए 85% के रियायती स्लैब की अनुमति दी जानी चाहिए।

18. अलग–अलग स्लैब के लिए टैरिफ संरचना और अलग–अलग दरें आम जनता के लिए टैरिफ को जटिल बना रही हैं। झारखंड, उड़ीसा और डीवीसी के समान टैरिफ संरचना और दरें बिहार में लागू की जा सकती हैं ताकि यहां खपत बढ़ सके।

19. एचटीएसएस टैरिफ को ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को भी अनुमति दी जानी चाहिए जैसा कि उद्योग विभाग द्वारा पहले ही सुझाव दिया गया है क्योंकि ऑक्सीजन संयंत्र में उत्पादन की प्रमुख लागत केवल ऊर्जा शुल्क है जो उत्पादन की कुल लागत का लगभग 75% है। यह क्षेत्र कोविड संकट प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं को जीवन रक्षक महत्वपूर्ण चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है।

अतः माननीय आयोग से अनुरोध करते हैं कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विद्युत शुल्क निर्धारित करते समय उपरोक्त सभी सुझावों को ध्यान में रखा जाए। साथ ही ऊर्जा की खपत बढ़ाने के साथ–साथ बिहार में आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए बिजली दरों को कम किया जाना चाहिए।

****

BCCI points to be circulated in public HEARING for Electricity Rates for FY 22-23

The electric distribution companies in Bihar i.e. North Bihar Power Distribution Co Ltd (NBPDCL) and South Bihar Power Distribution Co Ltd (SBPDCL) have submitted annual tariff petitions for FY 2022-23 which will be made applicable from 1 April 2022. In this regard, we have the following suggestions:-

1. Collection efficiency of South Bihar Power Distribution Company Limited in 2018-19 was 99.53% which come down to 73.74% in 2019-20 and 85.33% in 2020-21. This has led to very high Aggregate Transmission and Commercial (AT&C) losses. As Collection efficiency is a controllable factor, this should be improved on priority basis to prevent wastage of a valuable national resource.

2. Power supply should be made available 24x7, mainly to HT industrial units, which will result in increased revenue from sale of Power. It is well recognised by all policy makers that adequate power availability at viable cost and quality is a must for economic growth of Bihar. Therefore, all industrial consumers should be given highest priority in ensuring power availability. BERC should ensure that the high value paying consumers are not made uncompetitive and impose penalty on DISCOMS if uninterrupted power is not supplied to industrial units.

3. Distribution loss should be considered as approved by BERC at 15% and not as claimed by DISCOMS. Honest paying consumers should not be penalised by way of higher tariff because of failure of Discoms to control AT&C losses even after thousands of crores of public money has been spend to bring down losses.

4. In pre-payment system of power supply, we have to suggest that

   i. It should be optional

   ii To encourage the installation of pre-payment system, at least three (3) percent rebate in addition to the rebate of 1.5% for timely payment and 1.00% for online payment ie total 5.5% should be allowed.

   In the above context of rebate, Hon’ble BERC may like to revisit the study conducted for Forum of regulators (FOR) by Deloitte in which they have suggested to give a rebate of 5 to 6 percent in addition to the rebate being given to the post paid consumers.

   iii Further to remove the confusion of consumer regarding fast running of pre paid meters, the meter should be tested and test report should be made available to the consumer at the time of installation. Section 55 of the Act provides the procedure for installation of correct meter.

   iv Six (6) percent interest on advance payment and recharged amount should be allowed on reducing balance system and the limit of Rs 2000/- should be removed. There is no rationale for not allowing interest on amounts below Rs 2000/-.

   v Cost of the removed post paid meter should be reduced from the Assets of the licensees.

Contd……2

5. In spite of repeated orders from the Hon'ble Commission, SBPDCL and NBPDCL have not prepared the Asset Register as yet. It is not understood as to how they are working out the asset related cost and other parameters of the ARR.

6. As per the tariff petitions, about six (6) to eight (8) lakhs consumers are running without meter. This fact is very much surprising. However, instead of installing meters at such consumers, the DISCOMS are giving their full attention to replace the working meter by a prepaid meter in Patna and some other towns of Bihar. Continuing any unmetered connection and its tariff fixation is a violation of the provision of section 55 of The Act, and so the DISCOMS should provide meters to all unmetered consumers on priority basis.

7. In spite of constant monitoring by BERC, transmission & distribution loss has increased instead of decreasing. It is high time that BERC and State Govt impose personal penalties on the erring officers to control this wanton waste of precious national resource.

   Since the year 2006 i,e start of APDRP, the meter has been installed on Distribution Transformer. Recently executed schemes like IPDS, DDUGJY, RGGVY etc has provided considerable amount on installation of meter on Distribution Transformer (DTR). The main purpose was to recognise the particular DTR on which line loss was more. However, it would be well known to the Hon'ble Commission that whether the DISCOMS have carried such exercise to utilise the cost on DTR Metering. We therefore suggest that Hon'ble BERC should examine the utility of the installation of meter on DTR, and if there is no use of DTR metering, the whole project has been taken by DISCOMS will be a wastage of public money.

8. The erstwhile BSEB has already been restructured into various companies, with the stated objective of making the successor companies commercially viable. However, this objective has not been achieved as the discoms continue to be dominated by govt appointees. For achieving the objectives of restructuring, boards of these companies should be broad based to include industry & consumer representatives. MDs should have fixed tenures and long term viability plans should be formed and strictly implemented.

9. Presently, Electricity Duty is charged @ 6% on all consumers which is an unbearable burden, particularly on industrial consumers. This should be made part of GST, thus ensuring setoff. Alternatively, it should be reduced to 2 paise per unit for industrial consumers to make Industrial units competitive.

10. Currently, power can be purchased through Energy Exchanges at prices which are lower than long term agreements. Therefore, we request BERC and Discoms to upgrade their technical and managerial systems to take advantage of the same. This will enable them to bring down the cost of power, thus benefiting all consumers.

11. Open access should be actively promoted and the regulations should be rationalized by BERC to introduce pro-rata KVA charges. Without this, it will not be viable for any consumer to purchase open access power. This will benefit the Discoms also as their net power purchase cost will come down.

12. There is an urgent need to make the discoms customer focused. The website of the Discoms should have all relevant details of tariff and other norms. A training program for field officers should be held to educate them about the new regulations and make them responsive to customer needs. A centralised helpline and complaint redressal mechanism along with escalation system should be immediately introduced.

Contd……2

13. Any type of fixed charges should be completely faced out as discoms are now purchasing their entire power requirement. In the present era of national grid and purchase by discoms based on actual consumption only, Discoms should be requested to cancel excess PPA to reduce their fixed capacity charges.

14. HT consumers are still bearing the burden of cross subsidy of more than 20%. This is making them uncompetitive and has resulted in HT consumption to fall to as low as 9 to 10% of total units sold. Therefore, cross subsidy should be totally eliminated in 2 years and in this tariff, it should be reduced to max +-10%.

15. Load factor rebate should be made more attractive. The present load factor is very meager and hardly 1%+2% of energy bills of very few consumers. Present load factor rebate may be restructured to allow the same on actual consumed KVA and on entire energy charges. **All industrial consumers may be allowed 1% rebate for every 1% increase in LF beyond 30%, subject to maximum of 20%.** As load factor of consumers in HTSS is high, hence the min LF for them may be kept at 50%. This pattern is similar to that being currently followed in Jharkhand.

16. Presently in almost all HT consumers premises, sensitive and high quality meters have been installed which gives instantaneous reading of KVA, demand, power factor, KVAH, KWH and other billing parameters. This data is permanently stored in the meter which can be downloaded through MRI. Therefore, demand Based Tariff should be made applicable to all categories of consumers including HTSS consumers irrespective of their connected load. Remote meter reading has been introduced for all HT consumers and should be extended to all NDS consumers. Also, a copy of the MRI report should be given to all consumers along with the monthly energy bill.

18. To incentive increased unit consumption by HT consumers, the present TOD structure should be revised. The penal slab of 120% for 6hrs every day should be abolished. Also, the discounted slab of 85% should be allowed for 12 hrs from 11 PM to 11 AM.

19. The tariff structure and different rates for different slabs are complicating the tariff for the general public. Tariff structure and rates similar to that of Jharkhand, Orissa and DVC may be implemented in Bihar so that consumption can increase here.

20. HTSS tariff should also be allowed to oxygen producing plants as already suggested by Industries Dept as the major cost of production in oxygen plant is energy charges only which constitute about 75% of total cost of production. This sector is critical to covid crisis management as it supplies life saving vital medical oxygen to all hospitals and health services.

We request the Hon'ble Commission to take into account all the above suggestions while fixing the electric tariff for F/y 2022-23. Also, electricity rates should be reduced to increase energy consumption as well as ensure economic development in Bihar.

****